

जेटी आयकर आयुक्त, सूरत

बनाम

सहेली लीजिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड।

(2010 की सिविल अपील संख्या 4278)

7 मई, 2010

[के.जी.बालाकृष्णन सीजेआई, दीपक वर्मा और डॉ. बी.एस. चौहान,
जे.जे.]

आयकर अधिनियम, 1961 -एस.271 (1)(सी) - के तहत जुर्माना का उदग्रहण-निर्धारित आय शून्य या हानि है - की अनुमति- अभिनिर्धारित: जुमाना उदग्रहण योग्य है भले ही कोई कर देय ना हो।

निर्णय:

गूढ निर्णय -अभिनिर्धारित: माना गया: स्पष्टता के बिना संक्षिप्तता बेतुकेपन के दायरे में प्रवेश करने की संभावना है, जो अस्वीकार्य है - निर्णय लिखने के संबंध में दिशा निर्देश -दोहराया गया।

निर्णय लिखना - निर्णय लिखने के तरीके के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशानिर्देश-का पालन न करना - निंदा।

वर्तमान अपीलों में विचार के लिए प्रश्न यह था कि क्या आयकर अधिनियम की धारा 271(1)(सी) के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है, जहां मूल्यांकन की गई आय हानि है, इस तथ्य के बावजूद कि स्पष्टीकरण 4(ए) को इसमें जोड़ा गया था। अधिनियम और बाद में, आगे के खंड (ए) को एक अन्य एफ खंड (ए) से बदल दिया गया, जो प्रकृति में स्पष्ट है।

अपीलों को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1.1. उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 260 (ए) के तहत दायर अपील में उसके समक्ष पेश किए गए कानून के प्रश्न का निर्णय बहुत ही अनौपचारिक तरीके से किया है। यह आदेश न केवल गूढ़ है, बल्कि उन तर्कों से दूर-दूर तक निपटता नहीं है, जो राजस्व द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत करने की मांग की गई थी। यह सच है कि संक्षिप्तता एक कला है लेकिन स्पष्टता के बिना संक्षिप्तता का बेतुकेपन के दायरे में प्रवेश करने की संभावना है, जिसकी अनुमति नहीं है। आक्षेपित आदेश में यही दर्शाया गया है। इस न्यायालय ने बार-बार, न्यायिक कार्य करने वाली अदालतों को निर्णय/आदेश लिखने के तरीके की याद दिलाई, लेकिन समय-समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। इसलिए, न्यायालय एक बार फिर आदेशों और निर्णयों को लिखते समय उनका पालन करने के लिए न्यायालयों के

लिए कुछ दिशानिर्देशों को दोहराना चाहेगा। [पैरा 3, 4, 5 और 6]
[751 ई-एच; 752-ए] .

1.2. दिशानिर्देश प्रकृति में केवल उदाहरणात्मक हैं, संपूर्ण नहीं हैं और किसी दिए गए मामले की आवश्यकता को देखते हुए इसे और विस्तृत किया जा सकता है:

(i) निर्णय/आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जाना चाहिए, जो मामले के तथ्यों से संबंधित न हो। इसका लागू कानून और तथ्यों के साथ सह-संबंध होना चाहिए। निर्णय/आदेश में अनुपात निर्णय स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए।

(ii) मसौदा तैयार करने के बाद, यह पता लगाने के लिए उसका अध्ययन करना आवश्यक है कि क्या आवश्यक कोई भी चीज़ चर्चा से बच गई है।

(iii) अंतिम समाप्त निर्णय/आदेश में प्रवाह और घटनाओं का सही क्रम होना चाहिए, जो पाठक में रुचि पैदा करता रहेगा।

(iv) इस बात का उचित ध्यान रखा जाना चाहिए कि इसमें विषय पर सभी कानूनी ज्ञान का बोझ न डाला जाए क्योंकि बहुत अधिक निर्णयों का उद्धरण स्पष्टता के बजाय अधिक भ्रम पैदा करता है। सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि प्रमुख निर्णयों का उल्लेख किया जाना चाहिए और

उनके सुनाए जाने के बाद से जो विकास हुआ है, उसका उल्लेख किया जाना चाहिए और उसके बाद, नवीनतम निर्णय जिसमें पिछले सभी निर्णयों पर विचार किया गया है, का उल्लेख किया जाना चाहिए। निर्णय लिखते समय पाठक के मनोविज्ञान को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि उस संबंध में यथाशीघ्र और किसी भी स्थिति में तीन महीने की अवधि से अधिक नहीं। इसे लंबे समय तक लंबित रखने से वादकारियों और समाज में गलत संकेत जाता है।

(v) भाषा अलंकारिक नहीं होनी चाहिए और लेखक की और से किसी काल्पनिक प्रयास को प्रितिबिंबित नहीं करना चाहिए।

(vi) बहस समाप्त होने के बाद निर्णय सुनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। यथाशीघ्र और किसी भी स्थिति में तीन महीने की अवधि से अधिक नहीं। इसे लंबे समय तक लंबित रखने से वादकारियों और समाज में गलत संकेत जाता है।

(vii) ऐसे उदाहरण देने से बचना चाहिए, जिनसे सार्वजनिक या किसी विशेष समाज में आक्रोश पैदा होने की संभावना हो। इसमें ऐसा कुछ भी प्रितिबिंबित नहीं होना चाहिए जिससे किसी व्यक्ति या समाज की भावनाओं या भावनाओं को ठेस पहुंचे। [पैरा 7] [752-बी-एच; 753-ए-सी]

1.3. मौजूदा मामले में, कानून के महत्वपूर्ण सवाल और इसके व्यापक नतीजों पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच से यह कम से कम उम्मीद की गई थी कि न के कानून के सवाल को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे को अधिक गंभीरता से निपटाया है, जिसका उत्तर दिया जा रहा था। उच्च न्यायालय स्तर पर, जब किसी मामले पर डिवीजन बेंच द्वारा गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है, तो न केवल तथ्यात्मक बल्कि मामले के कानूनी पहलू पर भी कुछ हद तक विचार करना आवश्यक होता है। [पैरा 11 और 21] [754-सी; 756-एफ]

2.1. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 271(1)(सी) के पीछे का उद्देश्य निर्धारिती को (ए) आय के विवरण छुपाने और (बी) ऐसी आय के अपर्याप्त विवरण प्रस्तुत करने के लिए दंडित करना है। चाहे लौटाई गई आय लाभ हो या हानि, इसका वास्तव में कोई महत्व नहीं था। इसलिए, भले ही कोई कर देय नहीं था, जुर्माना अभी भी लगाया जा सकता था। उस संदर्भ में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि संशोधन से पहले भी इसका मतलब यह नहीं पढ़ा जा सकता था कि यदि रिटर्न दाखिल करने, नुकसान का खुलासा करने के कारण निर्धारिती द्वारा कोई कर देय नहीं था, तो निर्धारिती जुर्माना देने के लिए भी उत्तरदायी नहीं था। यदि निर्धारिती ने छुपाया था और/या अपर्याप्त विवरण प्रस्तुत किया था। [पैरा 24] [757 बी-सी]

2.2. कुछ उच्च न्यायालयों ने इसके विपरीत दृष्टिकोण, अपनाया था, इस प्रकार संसद ने अपने विवेक से "कोई भी" को "यदि कोई हो" से बदलकर स्थिति स्पष्ट करना उचित समझा। इस प्रकार, यह कोई ठोस संशोधन नहीं था। जिसने पहली बार जुर्माना लगाने का प्रावधान किया। प्रासंगिक वर्ष के वित्त अधिनियम द्वारा एक संशोधन जैसा कि खंडों पर नोट्स में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, यह दर्शाता है कि प्रस्तावित संशोधन प्रकृति में स्पष्टीकरणपूर्ण था और मूल्यांकन वर्ष 2003-2004 से पहले भी सभी मूल्यांकनों पर लागू होगा। [पैरा 25) (757-डी-ई]

2.3. भले ही निर्धारिती ने शून्य आय का खुलासा किया हो और रिकॉर्ड के सत्यापन पर, यह पाया जाता है कि कुछ आय छुपाई गई है या गलत तरीके से दिखाई गई है, उस स्थिति में भी जुर्माना लगाया जा सकता है। (पैरा 30) [759-डी]

सीआईटी बनाम गोल्ड कॉइन हेल्थ (पी) लिमिटेड (2008) 304 आईटी और 308 (एससी), पर निर्भर।

सीआईटी बनाम एलफिंस्टन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कंपनी लिमिटेड एक्सएल आईटी और 142, भिन्न किया।

वरचुअल सॉफ्ट सिस्टम्स लिमिटेड बनाम सीआईटी (2007) 289 आईटी और 83 एससी; सीआईटी बनाम हरप्रसाद एंड कंपनी पी. लिमिटेड

(1975) 99 आईटीऔर 118; रिलायंस जूट एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम सीआईटी (1979) 120 आईटीऔर 921, संदर्भित।

केस लॉ संदर्भ:

304 आईटीऔर 308 (एससी)	पर भरोसा किया	पैरा 19
सीआईटी(2007)289 आईटीऔर 83 एससी	संदर्भित	पैरा 20
(1975) 99 आईटीऔर 118	संदर्भित	पैरा 27
सीआईटी (1979) 120 आईटीऔर 921	संदर्भित किया	पैरा 27
एक्सएल आईटीऔर 142	भिन्न किया	पैरा 31

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्याएं। 2010 का 4278

अहमदाबाद में उच्च न्यायालय गुजरात के 2005 की अपील संख्या 1905 में पारित निर्णय और आदेश से दिनांक 08.08.2006 से ।

2010 के एच सी.ए. नं. 4279 के साथ

मोहन परासरन, एएसजी, वी शेखर, एच.और. राव, डी.एल. अपीलकर्ता की ओर से ए चिदानंद (बी.वी. बलराम दास के लिए)।

प्रतिवादी के लिए डी.एन.साहनी, भार्गव वी.देसाई, राहुल गुप्ता, निखिल शर्मा।

न्यायल्य द्वारा अभिनिर्धारित किया गया।

दीपक वर्मा, जे. 1. इजाजत स्वीकृत।

2. दोनों अपीलों के तथ्य समान होने के कारण, 2007 की एस.एल.पी.(सी) संख्या 5241 से उत्पन्न सिविल अपील के तथ्य को इस निर्णय में संदर्भित किया जा रहा है।

3. पहली बार में, 2005 के राजस्व कर अपील संख्या 1904 में पारित आक्षेपित आदेश के अवलोकन के बाद, अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा 2006 को निर्णय लिया गया, हमने मामले को नए सिरे से भेजने के बारे में सोचा। निर्णय गुण-दोष के आधार पर, कानून के अनुसार, लेकिन, गहराई से और अध्ययन की गई जांच के बाद, हमने सोचा कि क्षमा करने का निर्देश देने के बजाय, स्वयं गुण-दोष के आधार पर मामले पर विचार करना और इसमें शामिल कानूनी विवाद को शांत करना न्यायसंगत और उचित होगा। अपील में ऐसा इसलिए है क्योंकि डिवीजन बेंच ने आक्षेपित आदेश में कानून के प्रश्न का फैसला किया है जैसा कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 260 (ए) (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के तहत की गई अपील में उसके सामने पेश किया गया था। अत्यंत अनौपचारिक तरीके से. आदेश न केवल गूढ़ है, बल्कि उन तर्कों से दूर-दूर तक निपटता नहीं है, जिन्हें राजस्व द्वारा उसके समक्ष पेश करने की मांग की गई थी।

4. इस न्यायालय ने बार-बार न्यायिक कार्य करने वाले न्यायालयों को निर्णय/आदेश लिखने के तरीके की याद दिलाई है, लेकिन यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है।

5. इसमें कोई संदेह नहीं है, यह सच है कि संक्षिप्तता एक कला है लेकिन स्पष्टता के बिना संक्षिप्तता बेतुकेपन के दायरे में प्रवेश करने की संभावना है, जो अस्वीकार्य है। यह वही है जो आक्षेपित आदेश में प्रतिबिंबित हुआ है। जिसे हम बाद में यहां प्रस्तुत करेंगे।

6. इसलिए हम, गुण-दोष के आधार पर मामले पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ने से पहले, हम एक बार फिर न्यायालयों के लिए कुछ दिशानिर्देशों को दोहराना चाहेंगे, जबकि आदेश और निर्णय लिखते समय उनका पालन करना होगा।

7. ये दिशानिर्देश प्रकृति में केवल उदाहरणात्मक हैं, विस्तृत नहीं हैं और किसी दिए गए मामले की आवश्यकता और आवश्यकता को देखते हुए इसे और विस्तृत किया जा सकता है:

(ए) यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि निर्णय/आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जाना चाहिए, जो मामले के तथ्यों से मेल न खाता हो;

इसका लागू कानून एवं तथ्यों से सह-संबंध होना चाहिए। निर्णय/आदेश से अनुपात निर्णय स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए।

(बी) मसौदा तैयार करने के बाद, यह पता लगाने के लिए उसका अध्ययन करना आवश्यक है कि क्या उल्लेख करने योग्य कोई भी चीज़ चर्चा से बच गई है।

(सी) अंतिम रूप से समाप्त निर्णय/आदेश में कालक्रम कायम रहना चाहिए, इस अवधारणा को ध्यान में रखना चाहिए कि इसमें पठनीय, निरंतर रुचि है और किसी को इसे बीच में ही छोड़ने या छोड़ने का मन नहीं करता है। विस्तृत रूप से कहें तो इसमें प्रवाह और घटनाओं का सही क्रम होना चाहिए, जो पाठक में रुचि पैदा करता रहे।

(डी) इस बात का उचित ध्यान रखा जाना चाहिए कि इसमें विषय पर सभी कानूनी ज्ञान का बोझ न डाला जाए क्योंकि बहुत अधिक निर्णयों का उद्धरण स्पष्टता के बजाय अधिक भ्रम पैदा करता है। सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि प्रमुख निर्णयों का उल्लेख किया जाना चाहिए और उनके सुनाए जाने के बाद से जो विकास हुआ है, उसका उल्लेख किया जाना चाहिए और उसके बाद, नवीनतम निर्णय, जिसमें पिछले सभी निर्णयों पर विचार किया गया है, का उल्लेख किया जाना चाहिए। निर्णय

लिखते समय पाठक के मनोविज्ञान को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि उस संबंध में धारणा अनिवार्य है।

(ई) भाषा अलंकारिक नहीं होनी चाहिए और लेखक की ओर से किसी काल्पनिक प्रयास को प्रतिबिंबित नहीं करना चाहिए।

(एफ) बहस समाप्त होने के बाद, जल्द से जल्द निर्णय सुनाने का प्रयास किया जाना चाहिए और किसी भी मामले में तीन महीने की अवधि से अधिक नहीं। इसे लंबे समय तक लंबित रखने से पक्षकारान और समाज में गलत संकेत जाता है।

(जी) ऐसे उदाहरण देने से बचना चाहिए जिनसे सार्वजनिक या किसी विशेष समाज में आक्रोश पैदा होने की संभावना हो। इसमें ऐसा कुछ भी प्रतिबिंबित नहीं होना चाहिए जिससे किसी व्यक्ति या समाज की भावनाएं या भावनाओं को ठेस पहुंचे।

8. उपरोक्त कुछ दिशानिर्देश हैं जिन्हें निर्णय लिखते समय ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। वास्तव में, हम केवल वही दोहरा रहे हैं जो इस न्यायालय के कई निर्णयों में पहले ही कहा जा चुका है। .

9. उपरोक्त पृष्ठभूमि उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आक्षेपित निर्णय को पढ़ने के बाद दी गई है। कानून के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसा

कि अधिनियम की धारा 260 ए के तहत विचार किया गया है, का उत्तर देने के लिए इसे तैयार किया गया था:

क्या, तथ्यों और मामले की परिस्थितियों और कानून के आधार पर, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचने में सही है कि जहां मूल्यांकन की गई आय हानि है, वहां धारा 271(1)(सी) के तहत जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है। इस तथ्य के बावजूद कि 1.4.1976 से आयकर अधिनियम में स्पष्टीकरण 4 (ए) जोड़ा गया था और बाद में, आगे खंड (ए) को एक अन्य खंड (ए) से बदल दिया गया था जो स्पष्टीकरण प्रकृति में है , 1.4.2003 से प्रभावी।

10. हालाँकि, डिवीजन बेंच ने अपने विवेक से अपील को निम्नानुसार निपटाना उचित समझा:

"स्वीकृत तथ्य यह है कि अपीलकर्ता ने रिटर्न दाखिल किया है, घाटा और आय का "शून्य आय" के रूप में मूल्यांकन किया गया है। जब रिटर्न में नुकसान दिखाया गया हो और साथ ही आय का आकलन भी शून्य हो तो आयकर अधिनियम की धारा 271 (1) (सी) के तहत कोई जुर्माना नहीं लगता है। अपील स्वीकार करने का कोई

मामला नहीं बनता। अपील प्रवेश स्तर पर खारिज कर दी जाती है

11. कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न और इसके व्यापक परिणामों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच से यह उम्मीद कम ही थी कि वह इस मुद्दे को अधिक गंभीरता से निपटाती। कानून जिसका उत्तर इसके द्वारा दिया जा रहा था।

12. व्यथित महसूस करते हुए, यह अपील हमारे समक्ष रेवेन्यू द्वारा प्रस्तुत की गई है।

तथ्यात्मक मैट्रिक्स इस प्रकार है:

13. विपक्षी/निर्धारिती द्वारा रिटर्न दाखिल किए जाने पर, धारा 143 (3) के तहत एक आदेश अधिनियम 27.2.1998 को पारित किया गया था, जिसमें मूल्यांकन वर्ष 1995-1996 के लिए शून्य रुपये की कुल आय दिखाई गई थी।

14. मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान, यह देखा गया कि निर्धारिती ने मूल्यह्रास का दावा किया था, जिसे गलत माना गया था। इस प्रकार, 24,22,531/- रुपये की राशि को मूल्यह्रास से बाहर कर दिया गया। अधिनियम की धारा 271 (1) (सी) के तहत दंड की कार्यवाही शुरू की गई। राजस्व द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के जवाब में, निर्धारिती ने

अपना आवेदन दायर किया जवाब में आरोपों से इनकार किया गया और तर्क दिया गया कि पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जा सकता, जबकि लौटाई गई आय शून्य थी।

15. घाटे को कम करने में प्रभाव डालने वाली एक वस्तु के संबंध में जुर्माना लगाने की मांग की गई थी। उस मद के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की गई थी, जिसे आय में जोड़ा गया था जिसके कारण हानि कम हो गई थी। माना कि, निर्धारिती, एक पट्टे पर देने वाली कंपनी ने विभिन्न वस्तुओं पर संयंत्र और मशीनरी पर 100% की दर से मूल्यह्रास का दावा किया था। आय की गणना के साथ दाखिल किए गए मूल्यह्रास के विवरण में दावा 1,05,08,824/- रुपये दिखाया गया।

पूछताछ करने पर पता चला कि विभिन्न पक्षों के साथ किए गए लीज समझौतों के साथ 100% मूल्यह्रास का दावा किया गया था। हालाँकि, विभिन्न पक्षों के साथ किए गए लीज समझौतों की नियम और शर्तें समान थीं, सिवाय इसके कि पार्टियों के नाम बदल दिए गए थे। उक्त मूल्यह्रास की अस्वीकृति के बाद भी, निर्धारिती की कर योग्य आय शून्य थी और इसलिए, कोई कर देयता नहीं थी। निर्धारिती के अनुसार, ऐसे मामले में धारा 271 (1) (सी) के तहत कोई जुर्माना नहीं लगाया जा सकता था।

16. आयकर उपायुक्त, विशेष रेंज - 2, सूरत ने आदेश में चर्चा के आधार पर कहा कि निर्धारिती को आय में इस तरह के अतिरिक्त को उसकी कुल आय के रूप में मानने के संदर्भ में जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी था। अधिनियम की धारा 271 (1) (सी) के स्पष्टीकरण 4 (ए) का संदर्भ। तदनुसार छुपाई गयी आय 24,22,531/-पर शास्ति -न्यूनतम 100% कर की दर उदग्रहित की गई। इस प्रकार, करदाता पर 11,14,364/- का जुर्माना लगाया गया।

17. इससे व्यथित महसूस करते हुए, निर्धारिती ने आयकर आयुक्त (अपील-II) के समक्ष अपील दायर की। ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों पर विचार करते हुए, निर्धारिती की अपील खारिज कर दी गई और उस पर लगाए गए जुर्माने की पुष्टि की गई।

18. निर्धारिती ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, अहमदाबाद के समक्ष आगे अपील की। ट्रिब्यूनल, अप्सरा प्रोसेसर्स (पी) लिमिटेड और अन्य आईटीए संख्या 284/एएचडी./2004 दिनांक 17.12.2004 के मामले में अहमदाबाद ट्रिब्यूनल की विशेष पीठ द्वारा निष्कर्ष दिया गया कि कोई शास्ति उदग्रहित नहीं की जा सकती है यदि लौटाई गयी आय और मूल्यांकित आय हानि में है। तदनुसार आंकलन अधिकारी और आयुक्त (अपील्स) द्वारा पारित आदेश अपास्त और निरस्त किया गया और निर्धारिती पर उदग्रहित शास्ति निरस्त की गई। यह ट्रिब्यूनल का आदेश

था जिसे उच्च न्यायालय में अधिनियम की धारा 260 ए के तहत अपील दायर करके आगे बढ़ाया गया था, जिसे डिवीजन बेंच द्वारा बर्खास्तगी का सामना करना पड़ा।

19. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री वी. शेखर ने तर्क दिया कि इस अपील में पेश किए गए बिंदु का उत्तर राजस्व के पक्ष में इस न्यायालय के तीन विद्वान न्यायाधीशों की खंडपीठ के रिपोर्टेड फैसले (2008) 304 आईटी और 308 (एससी) शीर्षक सीआईटी बनाम गोल्ड कॉइन हेल्थ (पी) लिमिटेड में है।

20. गोल्ड कॉइन (सुप्रा) में इस न्यायालय का एक पूर्व निर्णय, (2007) 289 आईटी और 83 एससी में रिपोर्ट किया गया था, जिसका शीर्षक वर्चुअल सॉफ्ट सिस्टम्स लिमिटेड बनाम सीआईटी था, जिसे दो विद्वान न्यायाधीशों द्वारा निष्प्रभावी किया गया था।

21. यहां यह बताना उचित है कि गोल्ड कॉइन (सुप्रा) में, जिसे राजस्व द्वारा चुनौती दी जा रही थी, वह अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय की उसी पीठ द्वारा पारित आदेश था, जो पृष्ठ 309 पर जगह पाता है। जिसमें मामले का फैसला करने के लिए आगे बढ़ने से पहले, इस न्यायालय के तीन विद्वान न्यायाधीशों ने इसे पुनः पेश करना उचित समझा। उच्च न्यायालय के समक्ष गोल्ड कॉइन (सुप्रा) में प्रस्तुत कानून

का प्रश्न और इसमें प्रस्तुत कानून का प्रश्न अपील समान है लेकिन हमारे द्वारा जो समझा जा रहा है वह उस तरीके से है जिसमें एफ आक्षेपित निर्णय लिखा और सुनाया गया है। आखिरकार, उच्च न्यायालय स्तर पर, जब किसी मामले पर डिवीजन बेंच द्वारा गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है, तो न केवल तथ्यात्मक बल्कि यहां तक कि मामलों के कानूनी पहलू पर भी कुछ हद तक विचार करने की आवश्यकता है।

22.गोल्ड कोइन (सुप्रा) का मामला इस न्यायालय के तीन विद्वान न्यायाधीशों के समक्ष रखा गया था, क्योंकि वर्चुअल सॉफ्ट सिस्टम (सुप्रा) में इस न्यायालय के दो विद्वान न्यायाधीशों द्वारा पारित आदेश की शुद्धता और औचित्य पर संदेह था। इस प्रकार, कानून की सही व्याख्या पर संदेह को दूर करने के लिए, तीन न्यायाधीशों की एक पीठ का गठन किया गया जिसने सोने के सिक्के (सुप्रा) में मामले का फैसला किया।

23. यह देखा जाना चाहिए कि अधिनियम की धारा 271 (1)(सी) के पीछे का उद्देश्य निर्धारिती को -

(ए) आय के विवरण छुपाने और / या

(बी) इस आय का अपर्याप्त विवरण प्रस्तुत करना ।

24. लौटाई गई आय लाभ थी या हानि, इसका वास्तव में कोई महत्व नहीं था। इसलिए, भले ही कोई कर देय नहीं था, जुर्माना अभी भी

लगाया जा सकता था। इस संदर्भ में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि संशोधन से पहले भी इसका मतलब यह नहीं पढ़ा जा सकता था कि यदि रिटर्न दाखिल करने वाले निर्धारिती द्वारा कोई कर देय नहीं था, हानि का खुलासा करने के कारण, निर्धारिती भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं था। जुर्माना, भले ही निर्धारिती ने छुपाया हो और/या अपर्याप्त विवरण प्रस्तुत किया हो।

25. कुछ उच्च न्यायालयों ने इसके विपरीत दृष्टिकोण अपनाया था, इस प्रकार, संसद ने अपने विवेक से "कोई भी" को "यदि कोई हो" से बदलकर स्थिति स्पष्ट करना उचित समझा। इस प्रकार, यह कोई ठोस संशोधन नहीं था जिसने पहली बार जुर्माना लगाने का प्रावधान किया। प्रासंगिक वर्ष के वित्त अधिनियम द्वारा संशोधन, जैसा कि खंडों पर नोट्स में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, दर्शाता है कि प्रस्तावित संशोधन प्रकृति में स्पष्टीकरणपूर्ण था और मूल्यांकन वर्ष 2003-2004 से पहले भी सभी मूल्यांकनों पर लागू होगा।

26. इस प्रकार, गोल्ड कॉइन (सुप्रा) में, वांचू समिति की सिफारिशों और परिपत्र संख्या 204 दिनांक 24.7.1976 को संयुक्त रूप से पढ़ने के बाद, यह स्पष्ट किया गया कि खंड के स्पष्टीकरण 4 (ए) के संबंध में बिंदु स्पष्ट कर दिए गए हैं। 271(1)(सी)(iii) न केवल ऐसे मामले में जुर्माना लगाने का इरादा है जहां छुपाई गई आय को जोड़ने के बाद, मूल्यांकन के

बाद लौटाया गया नुकसान सकारात्मक आय बन जाता है, बल्कि ऐसे मामले में भी जहां छुपाई गई आय को जोड़ने से रिटर्न कम हो जाता है हानि और अंततः मूल्यांकन की गई आय भी हानि या ऋण का आंकड़ा है। इसलिए, 1.4.1976 और 1.4.2003 के बीच की अवधि के दौरान भी, स्थिति यह थी कि उस मामले में जुर्माना अभी भी लगाया जा सकता था, जहां छिपी हुई आय को जोड़ने से लौटाया गया नुकसान कम हो जाता है।

27. उपरोक्त मामले में, अधिनियम की धारा 2(24) में प्रदर्शित कानून में अभिव्यक्ति "आय" का अर्थ यह स्पष्ट किया गया है कि यह एक समावेशी परिभाषा है और इसमें नुकसान, यानी नकारात्मक लाभ शामिल है। इस न्यायालय के पहले के निर्णयों के आधार पर ऐसा माना गया है आयकर आयुक्त (केंद्रीय), दिल्ली बनाम हरप्रसाद एंड कंपनी_पी,लिमिटेड और अंदर चला गया रिलायंस जूट एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल,. विस्तृत और विस्तृत चर्चा के बाद, इस न्यायालय ने कानून के चार्जिंग प्रावधानों के संदर्भ में कहा कि अभिव्यक्ति "आय" को घाटे को शामिल करने के लिए समझा जाना चाहिए। अभिव्यक्ति "लाभ और लाभ" सकारात्मक आय को संदर्भित करती है जबकि "हानि" नकारात्मक लाभ या दूसरे शब्दों में शून्य आय को दर्शाती है।

28. मामले के इस पहलू पर अधिक विस्तार से विचार करते हुए, गोल्ड कॉइन (सुप्रा) ने वर्चुअल सॉफ्ट सिस्टम्स (सुप्रा) में दो विद्वान न्यायाधीशों द्वारा व्यक्त किए गए विचार को खारिज कर दिया।

29. आय और हानि से संबंधित गोल्ड कॉइन (सुप्रा) के प्रासंगिक पैरा 11 और 12 नीचे दिए गए हैं:

11. जब "आय" शब्द को हरप्रसाद के मामले में हुए नुकसान को शामिल करने के लिए पढ़ा जाता है, तो यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि उस मामले में भी जहां छिपी हुई आय को जोड़ने के कारण लौटाई गई हानि कम हो जाती है और भले ही अंतिम मूल्यांकन की गई आय हानि हो, फिर भी 1 अप्रैल 1976 से 1 अप्रैल 2003 की अवधि के दौरान भी उस पर जुर्माना लगाया जा सकता था। ऊपर उल्लिखित 24 जुलाई 1976 के परिपत्र में भी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (संक्षेप में "सीबीडीटी) द्वारा स्थिति स्पष्ट की गई थी "). यह कहा गया है कि ऐसे मामले में जहां निर्धारिती द्वारा आय के किसी अन्य प्रमुख के तहत किए गए या पिछले वर्षों से आगे लाए गए किसी भी नुकसान के खिलाफ छुपाई गई आय को समायोजित करने पर, कुल आय छिपी हुई आय से कम या यहां तक कि एक आंकड़े तक कम हो जाती है। माइनस अंक में जुर्माना लगाया जाएगा क्योंकि ऐसे मामले में 'जिस कर से बचने की कोशिश की गई है' वह छिपी हुई आय पर कर लगेगा जैसे कि यह "कुल आय" हो।

12. कानून अच्छी तरह से स्थापित है कि लागू प्रावधान कानून होगा क्योंकि यह रिटर्न दाखिल करने की तारीख पर मौजूद था। यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि जब किसी रिटर्न में कोई नुकसान लौटाया जाता है तो जरूरी नहीं कि वह संबंधित पिछले वर्ष का नुकसान हो। इसमें अग्रेषित हानि भी शामिल हो सकती है जिसे अधिनियम की धारा 72 के तहत भविष्य की आय के विरुद्ध स्थापित किया जाना आवश्यक है। इसलिए, रिटर्न दाखिल करने की तारीख पर लागू कानून को केवल पिछले लेखांकन वर्षों के नुकसान तक सीमित नहीं किया जा सकता है।

30. इसका आवश्यक परिणाम यह होगा कि भले ही निर्धारिती ने शून्य आय का खुलासा किया हो और रिकॉर्ड के सत्यापन पर, यह पाया जाता है कि कुछ आय छुपाई गई है या गलत तरीके से दिखाई गई है, उस स्थिति में भी जुर्माना लगाया जा सकता है। उपरोक्त स्थिति अब पूर्ण नहीं है और हमारे अनुसार, इसका उत्तर राजस्व के पक्ष में और निर्धारिती के विरुद्ध है।

31. प्रतिवादी निर्धारिती, श्री डीएन साहनी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि गोल्ड कॉइन (सुप्रा) में की गई टिप्पणियों को अधिक से अधिक ओबिटर के रूप में माना जा सकता है, लेकिन बाध्यकारी मिसाल के रूप में नहीं। उनके मुताबिक, कोऑर्डिनेट बेंच के पहले के फैसले में आयकर आयुक्त, बॉम्बे बनाम एलफिंस्टन स्पिनिंग

एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड,, अभी भी क्षेत्र में रहेगा और उक्त मामले के तथ्यों पर पूरी तरह से लागू होता है।

32. एल्फिंस्टन (सुप्रा) में निम्नलिखित टिप्पणियों पर बहुत जोर दिया गया है:

इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि कर निर्धारण कानून के शब्द विफल हो जाते हैं, तो कर उतना ही अधिक होगा। अदालतें, शायद ही कभी और स्पष्ट मामलों को छोड़कर, अनुकूल निर्माण द्वारा ड्राफ्ट्समैन की मदद नहीं कर सकती हैं। यहाँ कठिनाई केवल अशुद्ध भाषा की नहीं है। सच तो यह है कि बहुत बड़ी संख्या में करदाता शब्दों के दायरे में हैं लेकिन उनमें से कुछ नहीं हैं। क्या अधिनियम किसी अन्य आधार पर पिछले मामले में विफल हो सकता है (जैसा कि आज तय किए गए एक अन्य मामले में हुआ है) यह ऐसा मामला नहीं है जिस पर हम इस समय विचार कर रहे हैं। वहां यह कहना पर्याप्त है कि ये शब्द उन संशोधनों में शामिल नहीं हैं जो अपीलकर्ता के विद्वान वकील सुझाते हैं। "अतिरिक्त आयकर" अभिव्यक्ति में "अतिरिक्त" शब्द उस स्थिति को संदर्भित करना चाहिए जिसमें पहले कोई कर रहा हो। शब्द "कुल आय पर शुल्क" उस मामले का वर्णन करने के लिए उपयुक्त नहीं है जिसमें कोई आय नहीं है या हानि है। अभिव्यक्ति "कर के लिए उत्तरदायी लाभ" के मामले में भी यही स्थिति है। अंतिम

अभिव्यक्ति "ऐसे मुनाफे पर देय लाभांश" केवल तभी लागू हो सकता है जब लाभ हो, न कि तब जब कोई लाभ न हो।

यह स्पष्ट है कि विधायिका के मन में व्यक्तियों द्वारा अपनी आय के उचित हिस्से से अधिक लाभांश देने का मामला था। उन लोगों को छूट देने का इरादा था जो सीमा के भीतर रहते थे और उन लोगों पर बढ़ी हुई दर लगाई जानी थी जो इससे अधिक थे। कानून की गणना उन व्यक्तियों तक पहुंचने के लिए की गई थी, जिन्होंने उत्तरार्द्ध किया था, भले ही उन्होंने अगले वर्ष उसी लाभ का भुगतान करने के लिए छूट अर्जित करने के लिए एक वर्ष में लाभ को वापस रखने के उपकरण का सहारा लिया हो। इस प्रयोजन के लिए, पहले के वर्षों के मुनाफे को अगले वर्षों का मुनाफा माना गया। अब तक तो सब ठीक है। लेकिन विधानमंडल भारतीय आयकर अधिनियम की उस योजना में कानून को फिट करने में विफल रहा जिसके तहत और जिसे प्रभावी करने के लिए वित्त अधिनियम पारित किया गया है। विधानमंडल ने आय के लिए उपयुक्त भाषा का उपयोग किया, और दर को "कुल आय" पर लागू किया। जाहिर है, इसलिए, कानून उन मामलों में विफल हो जाना चाहिए जहां कोई कुल आय नहीं है, और अदालतों को विधायिका द्वारा की गई चूक की आपूर्ति करने के लिए आमंत्रित नहीं किया जा सकता है।

33. पहली नज़र में, दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार करने के बाद, हमने सोचा कि इस अपील में शामिल मुद्दे पर विचार करने के लिए मामले को एक बड़ी बेंच को भेजा जाना आवश्यक है, लेकिन गोल्ड कॉइन (सुप्रा) और एलफिंस्टन में निर्णयों की गहराई से जांच करने पर (सुप्रा), हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि गोल्ड कॉइन (सुप्रा) का अनुपात निर्णय पूरी तरह से मुद्दे को कवर करता है और एलफिंस्टन (सुप्रा) के मामले का उक्त मामले के तथ्यों पर कोई अनुप्रयोग नहीं है।

34. दोनों मामले निम्नलिखित व्यापक आधारों पर भिन्न हैं, अर्थात्:

(i) गोल्ड कॉइन हेल्थ (सुप्रा) आयकर अधिनियम, 1961 के तहत उत्पन्न हुआ, जबकि एलफिंस्टन (सुप्रा) 1922 के निरस्त आयकर अधिनियम के तहत उत्पन्न हुआ। (हालांकि यह केवल 2 निर्णयों में देखी गई एक विशिष्ट विशेषता है जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है) ।

(ii) गोल्ड कॉइन (सुप्रा) में जो प्रश्न विचाराधीन था वह यह था कि उसमें किए गए संशोधनों के संदर्भ में धारा 271(1)(सी) की सही व्याख्या क्या होगी, जबकि एलफिंस्टन (सुप्रा) में प्रश्न संबंधित था आयकर अधिनियम, 1922 की पहली अनुसूची के पैराग्राफ - बी के तहत निर्धारिती द्वारा अर्जित "लाभांश आय" पर "अतिरिक्त कर" की वसूली के लिए।

(iii) एलफिंस्टन (सुप्रा) ने पहली अनुसूची के पैरा-बी में आने वाले पांच शब्दों की व्याख्या की; "अतिरिक्त", "अतिरिक्त आयकर", "कुल आय पर शुल्क", "कर के लिए उत्तरदायी लाभ" और अंत में, "ऐसे मुनाफे से देय लाभांश", जबकि, गोल्ड कॉइन के मामले में, सवाल उठा कि क्या "आय" शब्द "इसमें धारा 271(1)(सी) के तहत जुर्माना लगाने के उद्देश्य से नुकसान शामिल है और यदि निर्धारिती को किसी विशेष वर्ष में नुकसान होता है तो क्या धारा 271(1)(सी) के तहत जुर्माना अभी भी उस पर लगाया जा सकता है। इसका उत्तर गोल्ड कॉइन (सुप्रा) में राजस्व के पक्ष में और निर्धारिती के विरुद्ध स्पष्ट रूप से दिया गया है।

(iv) जुर्माना लगाने का उद्देश्य किसी भी चार्जिंग अनुभाग के तहत कर या अतिरिक्त कर का भुगतान करने के लिए निर्धारिती की देनदारी निर्धारित करने से अलग है। इस प्रकार, दंड प्रावधान पर लागू व्याख्या को आयकर या अतिरिक्त कर के भुगतान के लिए किसी भी चार्जिंग अनुभाग की व्याख्या करते समय लागू नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, दोनों प्रावधानों यानी जुर्माना और चार्ज के अलग-अलग उद्देश्य और परिणाम हैं। वे निर्धारिती के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं।

(v) लाभांश से अर्जित आय पर पहली अनुसूची के तहत अतिरिक्त कर का भुगतान करने का दायित्व यह दर्शाता है कि निर्धारिती को पहले "कर" का भुगतान करना होगा और फिर निर्दिष्ट आय पर अतिरिक्त कर का

भुगतान करना होगा। यह मूल रूप से यह मुद्दा था जिसकी जांच एलफिंस्टन (सुप्रा) में की गई थी जिसमें उनके आधिपत्य ने अनुसूची के पहले पैराग्राफ को अधिनियमित करने के उद्देश्य पर विचार किया था। इस वस्तु का दंड प्रावधानों से कोई लेना-देना नहीं है।

(vi) अधिनियम की एक धारा में आने वाला एक विशेष शब्द, जिसका एक विशेष उद्देश्य होता है, एक ही अधिनियम की विभिन्न धाराओं में उपयोग किए जाने पर एक ही अर्थ नहीं ले सकता है, जो विभिन्न उद्देश्य के लिए अधिनियमित किया गया है। दूसरे शब्दों में, अधिनियम की विभिन्न धाराओं में आने वाले एक शब्द का अलग-अलग अर्थ हो सकता है, यदि दोनों धाराओं का उद्देश्य अलग-अलग है और जब दोनों अलग-अलग क्षेत्रों में कार्य करते हैं।

(vii) इस अपील में शामिल कानून का प्रश्न सीधे गोल्ड कॉइन (सुप्रा) के निर्णय द्वारा कवर किया गया है और तदनुसार उत्तर दिया जाना है।

(viii) इसलिए, एलफिंस्टन (सुप्रा) का गोल्ड कॉइन (सुप्रा) मामले में लिए गए दृष्टिकोण से कोई लेना-देना नहीं है और अगर इस पर ध्यान दिया गया होता, तो भी उपरोक्त विशिष्ट विशेषता के कारण इसमें लिया गया निर्णय वही होता।

(ix) गोल्ड कोइन (सुप्रा) से जुड़ा मामला एलफिंस्टन (सुप्रा) से जुड़ा मुद्दा पूरी तरह से अलग है, दोनों निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण संबंधित क्षेत्रों में सही ढंग से काम कर रहा है, इसलिए मामले पर पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है।

(x) न्यायालय को किसी मामले को पुनर्विचार के लिए बड़ी पीठ के पास भेजने में सक्षम बनाने के लिए, यह बताना आवश्यक है कि संबंधित मुद्दे से संबंधित कानून के विशेष प्रावधान पर ध्यान नहीं दिया गया था या उसमें कोई स्पष्ट त्रुटि है। इसका चेहरा या कि किसी विशेष पूर्व निर्णय पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसका सीधा संबंध है या जिसने विपरीत दृष्टिकोण अपनाया है। यहां ऐसा कोई मामला प्रतीत नहीं होता। इस प्रकार, जैसा कि हमारी सुविचारित राय है, इसे किसी बड़ी पीठ के पास भेजने की आवश्यकता नहीं है; यह गोल्ड कोइन (सुप्रा) में इस न्यायालय के फैसले द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है।

35. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि एलफिंस्टन (सुप्रा) के अनुपात का मामले के तथ्यों पर कोई अनुप्रयोग नहीं है और कानून के प्रश्न का राजस्व के पक्ष में और विपक्ष में स्पष्ट रूप से उत्तर दिया गया है। गोल्ड कोइन में निर्धारिती (सुप्रा) के परिणामस्वरूप, राजस्व द्वारा अपील की अनुमति दी जाती है। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित और डिवीजन बेंच द्वारा पुष्टि किए गए विवादित

आदेश को रद्द कर दिया गया है। इसलिए, राजस्व कानून के अनुसार गुण-दोष के आधार पर निर्धारिती के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र होगा।

36. जैसा कि ऊपर बताया गया है, अपीलें स्वीकार की जाएंगी लेकिन खर्चे के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

के.के.टी.

अपील स्वीकृत

यह अनुवाद ऑर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्रीमती शशि गजराना (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।